

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1013

(जिसका उत्तर 04 दिसम्बर, 2015/13 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

सरकारी बैंकों हेतु इंद्रधनुष योजना

1013. कुमारी सुष्मिता देव:	श्रीमती आर. वनरोजा:
श्री राजेश रंजन:	श्रीमती वी. सत्यबामा:
डॉ. भोला सिंह:	प्रो. के. वी. थॉमस:
श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:	श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:	श्री संजय धोत्रे:
श्री ए. अरुणमणिदेवन:	श्री कारादी सनगन्ना अमरप्पा:
श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी:	श्री दुष्यंत चौटाला:
श्री रायपति सम्बासिवा राव:	

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने 'इंद्रधनुष' नामक एक योजना सभी सरकारी क्षेत्रक बैंकों की कुशलता और कार्यकरण को सुधारने के लिए घोषित की है जिससे उनकी गैर-निष्पादनकारी आस्तियां (एनपीए) कम हों और यदि हां, तो इसके प्रमुख लक्ष्य क्या हैं;
- (ख) क्या ऋणों के भुगतान में गंभीर और जटिल समस्याओं का कारण बैंकिंग प्रणाली में कतिपय कमियों से हो सकता है जो दिन प्रतिदिन गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को बढ़ा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) कुल एनपीए का ब्यौरा और स्थिति क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वसूल किए गए/माफ की गई ऋण राशि बैंक और राज्य-वार कितनी है;
- (घ) मामले जिनमें सामरिक ऋण पुनर्गठन योजना, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन तथा प्रतिभूति ब्याजों का बैंकों द्वारा नुकसानदायी आस्तियों को पुनर्जीवित करने हेतु लागू करना (सरफेस) शुरू किया गया है, की संख्या कितनी है; और
- (ड.) सरकार द्वारा पीएसबी के एनपीए को घटाने के लिए क्या अन्य उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क) और (ख): भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों (पीएसबी) में उनकी अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को घटाने के उद्देश्य सहित उनकी दक्षता और कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए "इंद्रधनुष" नामक एक योजना की घोषणा की है।

कई कारकों के कारण परियोजनाएं निरंतर अवरूद्ध/दबावग्रस्त हो रही हैं, इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप बैंकों पर एनपीए का भार बढ़ा है। हाल की समीक्षा में, विद्युत, इस्पात तथा सड़क क्षेत्रों में दबाव का कारण बन रही समस्याओं की जांच की गयी थी। यह पाया गया था कि इन परियोजनाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण विभिन्न सरकारी तथा विनियामकीय एजेंसियों से परमिट तथा अनुमोदन प्राप्त करने, तथा भूमि अधिग्रहण में देरी, वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) में देरी करना; कोयला तथा गैस दोनों ईंधन की उपलब्धता में कमी; कोयला ब्लाकों को रद्द करना; लोह अयस्क खादानों को बंद करने से परियोजना की व्यवहार्यता का प्रभावित होना; पारेषण क्षमता में कमी; अपनी खरीद क्षमता घटने के कारण डिस्कॉम द्वारा विद्युत की सीमित खरीद; अतिरिक्त इक्विटी जुटाने के लिए प्रवर्तकों की सीमित क्षमता द्वारा वित्तपोषण अंतराल की स्थिति सामने आना तथा उच्च लेवरेज अनुपात को देखते हुए बैंकों द्वारा उनके ऋण जोखिम को बढ़ाने में असमर्थता; विनियामकीय बाध्यताओं के कारण व्यवहार्य पाई गई परियोजनाओं की पुनर्संरचना में बैंकों की अक्षमता थी।

(ग): विवरण अनुबंध पर हैं।

(घ): उन मामलों की संख्या, जिनमें कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना की जा चुकी है तथा जिन मामलों में दबावग्रस्त आस्तियों के पुनरुज्जीवन हेतु बैंकों द्वारा उठाए गए वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफासी) के तहत कार्रवाई की गई है, निम्नानुसार है:

	कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना	सरफासी
मामलों की संख्या	66	317181

(ङ.): सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, 'वास्तविक रूप से अपूर्ण तथा लटकी हुई' राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाएं या परियोजनाओं को पुनरुज्जीवित करने के लिए एकबारगी वित्तीय सहायता, हानि में चल रहे राज्य डिस्कॉम सेवाओं को पुनरुज्जीवित करने के लिए 3.27 लाख करोड़ रुपए की (बैंकों से 1.95 लाख करोड़ रुपए सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों से) ऋण पुनर्संरचना तथा सुधार पैकेज तथा घरेलू इस्पात उत्पादकों को डम्पिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद करने हेतु इस्पात पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है।

आरबीआई ने विनियामक के रूप में दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय दबाव की आरंभ में पहचान करने, समाधान के त्वरित उपाय, उधारदाताओं के लिए उचित वसूली, अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों के पुनर्सुदृढीकरण के लिए संरचना – संयुक्त उधारदाता मंच (जेएलएफ) संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा तथा सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) शामिल है।

को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान सकल एनपीए तथा वसूलियों पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बैंक-वार विवरण (करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सकल एनपीए				समझौता सहित बट्टे खाते डालना				कुल एनपीए कटौती			
		2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
1	इलाहाबाद बैंक	2,059	5,137	8,068	8,358	1,001	1,352	782	2,109	1,821	2,814	3,090	4,736
2	आन्धा बैंक	1,798	3,714	5,858	6,877	169	334	263	1,124	485	825	689	2,405
3	बैंक आफ बड़ौदा	4,465	7,983	11,876	16,261	1,215	2,356	964	1,564	2,131	3,326	2,941	4,130
4	बैंक आफ इंडिया	5,894	8,765	11,869	22,193	2,415	2,415	1,767	801	4,107	4,419	5,708	6,327
5	बैंक आफ महाराष्ट्र	1,297	1,138	2,860	6,402	395	663	401	264	753	967	867	1,091
6	भारतीय महिला बैंक लि.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	केनरा बैंक	4,032	6,260	7,570	13,040	1,460	1,535	1,591	1,472	3,695	3,591	7,134	5,400
8	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	7,273	8,456	11,500	11,873	629	1,061	1,995	1,386	1,970	3,942	4,525	6,206
9	कार्पोरेशन बैंक	1,274	2,048	4,737	7,107	565	709	463	779	719	1,023	867	1,369
10	देना बैंक	957	1,452	2,616	4,393	194	237	479	515	608	624	1,256	1,897
11	आईडीबीआई बैंक लि.	4,551	6,450	9,960	12,685	319	383	1,393	1,609	794	841	2,196	3,376
12	इंडियन बैंक	1,851	3,565	4,562	5,670	506	520	628	550	769	1,178	1,836	2,231
13	इण्डियन ओवरसीज बैंक	3,920	6,608	9,020	14,922	1,166	1,642	1,474	3,131	2,354	2,913	4,490	6,114
14	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	3,580	4,184	5,618	7,666	933	1,416	1,252	925	2,238	2,610	2,593	2,466
15	पंजाब एंड सिंध बैंक	763	1,537	2,554	3,082	39	50	204	263	212	320	603	714
16	पंजाब नेशनल बैंक	8,720	13,466	18,880	25,695	126	997	1,947	6,587	2,331	3,901	5,396	9,845
17	सिंडिकेट बैंक	3,183	2,979	4,611	6,442	891	1,297	1,025	1,527	2,573	2,347	2,062	3,669
18	यूको बैंक	4,086	7,130	6,621	10,265	391	617	1,423	1,401	1,465	2,118	4,470	3,908
19	यूनियन बैंक आफ इंडिया	5,450	6,314	9,564	13,031	938	1,129	913	931	1,933	3,110	2,229	2,199
20	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	2,176	2,964	7,118	6,553	233	1,094	481	761	1,144	1,697	3,853	4,652
21	विजया बैंक	1,718	1,533	1,986	2,443	214	543	296	791	1,598	1,787	1,721	2,370
22	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	1,651	2,119	2,733	2,945	275	463	399	363	756	1,160	1,510	1,475
23	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	2,007	3,186	5,824	4,985	265	343	31	355	1,362	1,638	2,184	3,889
24	भारतीय स्टेट बैंक	39,676	51,189	61,605	56,725	744	5,594	13,177	21,313	10,362	20,480	31,100	34,324
25	स्टेट बैंक आफ इंदौर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	स्टेट बैंक आफ मैसूर	1,503	2,081	2,819	2,136	165	275	403	740	672	1,080	1,359	2,578
27	स्टेट बैंक आफ पटियाला	1,888	2,453	3,758	4,360	120	28	463	755	1,061	1,469	2,759	4,107
28	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	1,489	1,750	3,077	2,357	182	176	196	526	2,087	2,145	3,605	5,195
सरकारी क्षेत्र के बैंक		1,17,262	1,64,462	2,27,264	2,78,468	15,551	27,231	34,409	52,542	49,999	72,324	1,01,042	1,26,671

स्रोत: आरबीआई - ऑफ-साइट तुलन-पत्र ब्यौरा (वार्षिक ब्यौरा), बैंकों द्वारा यथा सूचित, वैश्विक परिचालन।